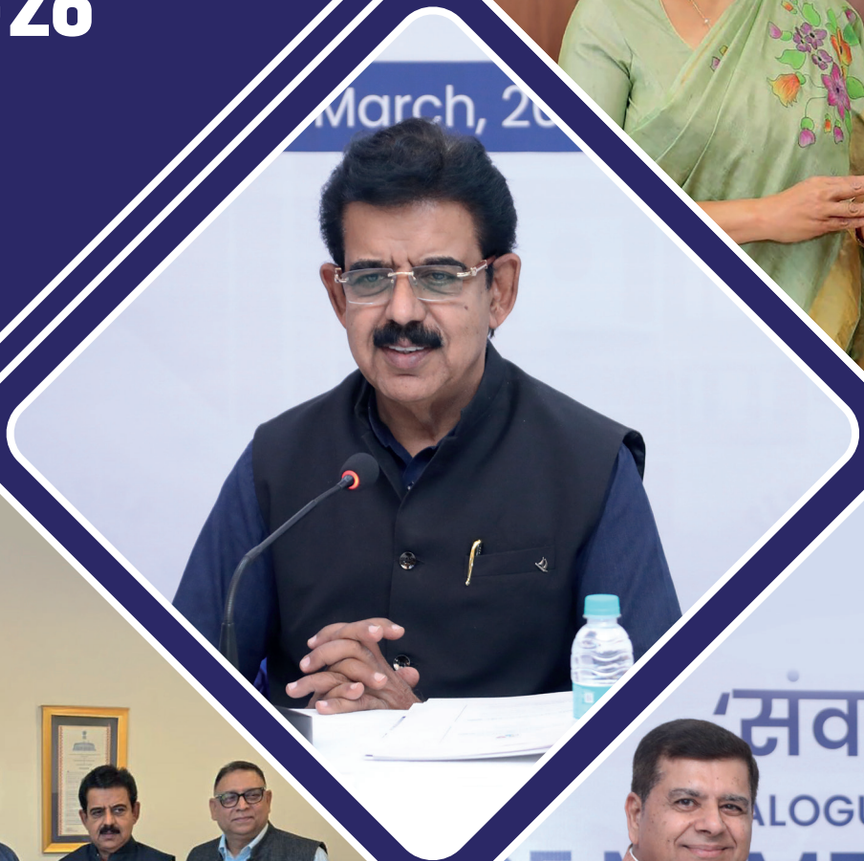
वार्षिक सारांश
YEARLY ROUNDUP
2025-26









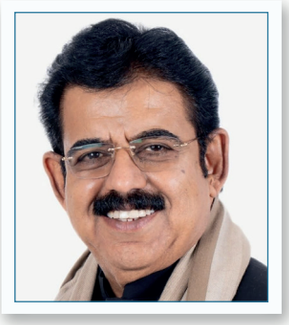


FRIENDS OF MSMEs
IN PARLIAMENT

Leadership Perspective

नेतृत्व के विचार

"The MSME sector is a cornerstone of India's vision of becoming a developed nation by 2047, driving employment generation, innovation, entrepreneurship, and accelerating the journey towards Atmanirbhar Bharat. Through 'Friends of MSMEs in Parliament', we have fostered a culture of collaboration and partnership by bringing together industry associations, entrepreneurs, and policymakers on a common national platform. We have made meaningful contributions to advancing important reforms, including abolition of Bank Loan Ratings. Going forward, our focus is on accelerating Third Generation Reforms to create a more technology-enabled, and industry-friendly regulatory environment that promotes investment, innovation, and global competitiveness of Indian enterprises, while making a decisive contribution towards realizing the vision of Viksit Bharat 2047."



Shri Shankar Lalwani
Chairman and MP, (Indore)

"एमएसएमई क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की राष्ट्रीय परिकल्पना का प्रमुख आधार है तथा रोजगार सृजन, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत को नई गति प्रदान कर रहा है। 'फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट' के माध्यम से, उद्योग संगठनों, उद्यमियों और नीति-निर्माताओं को एक साझा राष्ट्रीय मंच पर जोड़कर सहयोग, संवाद और सहभागिता की सशक्त संस्कृति को प्रोत्साहित किया गया है, जिससे भारत की औद्योगिक प्रगति और आर्थिक विकास को नई दिशा मिली है। बैंक ऋण रेटिंग की समाप्ति जैसे महत्वपूर्ण सुधारों को आगे बढ़ाने में भी सार्थक योगदान दिया गया है। हमारा संकल्प Third Generation Reforms को गति देने पर है, ताकि प्रौद्योगिकी-सक्षम, उद्योग-अनुकूल और निवेश एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला नियामक वातावरण विकसित किया जा सके। इससे भारतीय उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सुदृढ़ होगी और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में निर्णायक योगदान सुनिश्चित होगा।"

"Fostering youth entrepreneurship and strengthening MSMEs are critical to generate large-scale employment India needs each year. Over the past three years, our forum has amplified the voice of small manufacturers in Parliament, advocating key Third Generation Reforms to address systemic challenges. Going forward, our forum remains committed to build an ecosystem that promotes ease of doing business through reduced compliance burdens and better access to finance, skills, and markets, while empowering young entrepreneurs to create sustainable and globally competitive enterprises."



Shri Rajendra Agrawal
Convenor and Former MP, (Meerut)

"युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना, भारत में प्रतिवर्ष आवश्यक बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले तीन वर्षों में हमारे मंच ने संसद में लघु विनिर्माताओं की आवाज़ को प्रभावी ढंग से उठाया है तथा संरचनात्मक चुनौतियों के समाधान हेतु महत्वपूर्ण तृतीय पीढ़ी के सुधारों की की आवश्यकता पर निरंतर बल दिया है। हमारा मंच अनुपालन संबंधी बोझ को कम कर, वित्त, कौशल और बाज़ार तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करते हुए, व्यवसाय सुगमता को बढ़ावा देने वाला एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने तथा युवा उद्यमियों को टिकाऊ और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्यम स्थापित करने के लिए सशक्त बनाने के प्रति प्रतिबद्ध है।"

Background

पृष्ठभूमि



The need for massive job creation is being felt in India. The large corporate sector is increasingly adopting capital intensive automized processes shredding workforce. The only way forward for creating jobs is through self-employment and creation of MSMEs. That is the only hope for millions of students graduating out of colleges also. However, both new and existing entrepreneurs face enormous challenges.

Almost all MPs, cutting across party lines, are sympathetic to their problems but have not been able to lend effective support to the MSME sector. There is a realization that MSMEs have not been able to leverage the Parliamentary system to clear their way to realize their maximum potential. A like-minded group of Members of Parliament -from both Lok Sabha and Rajya Sabha, have come forward to form a Group in the name of 'Friends of MSMEs in Parliament' to address the constraint and be a bridge between the MSMEs and the Parliament.

भारत के संदर्भ में व्यापक स्तर पर रोज़गार सृजन की आवश्यकता को अत्यधिक महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकारें अपने आकार को घटा रही हैं। और बड़ा कॉर्पोरेट क्षेत्र भी तेजी से पूंजी-प्रधान और स्वचालित प्रक्रियाएं अपना रहा है, जिससे कार्यबल कम होता जा रहा है। रोज़गार सृजन का एकमात्र रास्ता स्वरोज़गार और MSMEs के निर्माण के माध्यम से ही संभव है। यही करोड़ों छात्रों के लिए भी एकमात्र आशा है, जो हर साल कॉलेजों से स्नातक होकर निकलते हैं।

नए और पहले से स्थापित दोनों ही उद्यमियों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लगभग सभी सांसद, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनकी समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन MSME क्षेत्र को प्रभावी सहायता देने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि MSMEs संसदीय व्यवस्था का उपयोग अपनी पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए नहीं कर पाए हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के समान विचारधारा वाले सांसदों के एक समूह बनाने के लिए पहल की है, ताकि एमएसएमई और संसद के बीच एक सेतु का काम किया जा सके।

FRIENDS OF MSMEs
IN PARLIAMENT

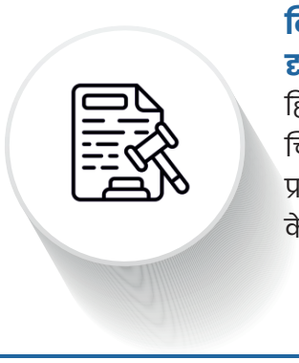
Secretary: Rishabh Gaur | **Mobile:** 9027766616 | **E-Mail:** secretary@friendsofmsme.org.in
Secretariat: FISME, B- 4/161 Safdarjung Enclave, New Delhi – 110029, India

Objectives

उद्देश्य

Ensuring Legislation incorporate MSME perspective

To interact with stakeholders, gather their concerns and aspirations and to voice them in the Parliament through a structured process during every Session of Parliament



विधायी प्रक्रियाओं में एमएसएमई का दृष्टिकोण शामिल करना सुनिश्चित करना

हितधारकों के साथ संवाद स्थापित करना, उनकी चिंताओं और अपेक्षाओं को एकत्रित करना तथा प्रत्येक संसद सत्र के दौरान एक संरचित प्रक्रिया के माध्यम से उन्हें संसद में प्रस्तुत करना।

Leveraging Parliamentary Institutions for benefit of MSMEs

To leverage Parliamentary institutions such as Departments, related Parliamentary Standing Committees in resolving MSME issues

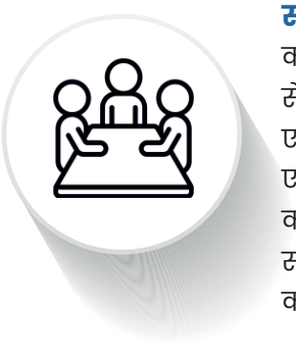


एमएसएमई के हित में संसदीय संस्थाओं का उपयोग करना

एमएसएमई से जुड़ी समस्याओं के समाधान में विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों जैसी संसदीय संस्थाओं का प्रभावी रूप से उपयोग करना।

Facilitating dialogue with Govt, institutions and MSMEs

To review efficacy of MSME related provisions of legislations & policies with MSME leaders and lend support for holding dialogue with respective Ministries/ Departments and institutions for improving outcomes for MSMEs



सरकार, संस्थानों एवं MSMEs के बीच संवाद को सुगम बनाना

कानूनों और नीतियों में शामिल एमएसएमई से संबंधित प्रावधानों की प्रभावशीलता की एमएसएमई नेताओं के साथ समीक्षा करना और एमएसएमई के लिए बेहतर परिणाम सुनिश्चित करने हेतु संबंधित मंत्रालयों, और संस्थाओं के साथ संवाद स्थापित करने में सहयोग प्रदान करना।

Bridging the Information Gap Between MSMEs and Government

Bridging the Information gap by disseminating key initiatives undertaken by the Government, particularly those aimed at strengthening the MSME ecosystem



एमएसएमई एवं सरकार के बीच सूचना आदान-प्रदान को सुदृढ़ बनाना

एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलों की जानकारी का प्रसार कर सूचना अंतराल को कम करना।



SAMWAD: Dialogue with Parliamentarians

Key Issues Discussed

Key issues discussed include challenges related to Access to Finance, such as banks' prepayment and foreclosure charges (ranging from 2-4%), restrictions posed by Third-Party Credit Ratings, and the demanding requirement of Bank Guarantees for MSMEs. The deliberations also covered Recommendations of the ruling party.

Key Outcomes

Key outcomes include the conceptualization and operationalization of the 'Friends of MSMEs' forum, alongside the establishment of a dedicated Banking Grievance Redressal Portal for MSMEs. Significant progress was made through representations to the Parliamentary Standing Committee on Finance and a meeting with the Hon'ble Minister of Finance. Furthermore, MSME-related recommendations were successfully incorporated into the Election Manifesto 2024. A notable event was the Seminar on Reducing Cost of Litigation, presided over by Shri Arjun Ram Meghwal, Union Minister of State (I/C) for Law & Justice.





SAMWAD: सांसदों के साथ संवाद

चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दे

चर्चा किए गए प्रमुख मुद्दों में वित्त तक पहुँचने से संबंधित चुनौतियाँ शामिल हैं, जैसे कि बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले प्रीपेमेंट और फोरक्लोजर शुल्क (2-4%), थर्ड-पार्टी क्रेडिट रेटिंग द्वारा MSMEs की वित्त तक पहुँच को प्रतिबंधित करना, और बैंक गारंटियों की अनिवार्य आवश्यकता। विमर्श के दौरान सत्तारूढ़ दल की अनुशंसाओं पर भी चर्चा की गई।

मुख्य निष्कर्ष

प्रमुख उपलब्धियों में 'फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़' मंच की शुरुआत तथा एमएसएमई के लिए समर्पित बैंकिंग शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना शामिल रही। वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति एवं माननीय वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्तुतियों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रगति हुई। साथ ही, एमएसएमई से संबंधित कई सिफारिशों को चुनाव घोषणा-पत्र 2024 में शामिल कराया गया। इसके अतिरिक्त, "मुकदमेबाजी की लागत में कमी" विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने की।



Key Initiatives in 2023-24

2023–24 में प्रमुख पहलें





Study on Identifying Strategies for Quadrupling Meerut's GDP. Study was released by Shri Pankaj Chaudhary, Hon'ble Union Minister of State (Finance); Shri Rajendra Agrawal, Convenor of Friends of MSMEs in Parliament and Former MP from Meerut; and Shri Harikant Ahluwalia, Mayor of Meerut.

मेरठ की जीडीपी को चार गुना बढ़ाने की रणनीतियों पर अध्ययन तैयार किया गया, जिसका विमोचन माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी, फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट के संयोजक एवं मेरठ के पूर्व सांसद श्री राजेन्द्र अग्रवाल, तथा मेरठ के महापौर श्री हरिकांत अहलूवालिया द्वारा किया गया।

Meeting with Hon'ble Minister of Finance: A delegation led by Shri Rajendra Agarwal, Convenor of 'Friends of MSMEs in Parliament,' met Hon'ble Minister of Finance Nirmala Sitharaman to advocate for prioritization of medium-sized enterprises in economic policy.

माननीय वित्त मंत्री से भेंट: 'फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट' के संयोजक श्री राजेन्द्र अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर आर्थिक नीतियों में मध्यम उद्यमों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

Dialogue With IIT Madras on Startups and Enhancing Export Competitiveness: This event brought together members of 'Friends of MSMEs in Parliament,' FISME office bearers, and a delegation of 80 students and research scholars from IIT Madras's Public Policy Club. The discussion spanned various critical issues for MSMEs, including business challenges and opportunities, start-up collaboration, and the growth of the textile industry.

स्टार्टअप्स एवं निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर आईआईटी मद्रास के साथ संवाद: इस कार्यक्रम में 'फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट' के सदस्यों, FISME के पदाधिकारियों तथा आईआईटी मद्रास के पब्लिक पॉलिसी क्लब के 80 विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों ने भाग लिया। चर्चा में एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों एवं अवसरों, स्टार्टअप सहयोग, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता तथा वस्त्र उद्योग के विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया गया।









SAMWAD: Dialogue with Parliamentarians

Key Issues Discussed

4 SAMWAD dialogues were held in 2024-25. Key issues discussed included SMA provisions, delayed payments, and issues related to the arbitration process. Parliamentarians highlighted the urgent need to revive the manufacturing sector and promote self-employment. Concerns were specifically raised regarding the impact of anti-dumping and safeguard duties on raw materials, which inadvertently make Indian MSMEs less competitive. It was proposed that the 'Friends of MSMEs in Parliament' forum take on a mentorship role to support MSMEs.

Key Outcomes

A memorandum was prepared for Parliamentary Standing Committee on Finance. This memorandum addressed a range of pressing concerns for MSMEs, such as the intricacies of SMA framework, issues related to Bank Loan Ratings (BLR), challenges in bank grievance redressal mechanisms, and the contentious nature of charges on loan prepayment or foreclosure. Forum also deliberated on the need to balance the often-conflicting interests of large raw material producers and MSMEs.

SAMWAD: सांसदों के साथ संवाद

चर्चा के प्रमुख मुद्दे

वर्ष 2024-25 में 4 संवाद (SAMWAD) कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें एसएमए प्रावधानों, विलंबित भुगतानों तथा मध्यस्थता प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा हुई। सांसदों ने विनिर्माण क्षेत्र के पुनरुद्धार और स्व-रोजगार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया। कच्चे माल पर एंटी-डंपिंग एवं सेफगार्ड शुल्कों के कारण एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होने पर भी चिंता व्यक्त की गई। साथ ही, 'फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट' मंच को एमएसएमई के लिए मार्गदर्शक (मेंटॉर) की भूमिका निभाने का सुझाव दिया गया।

प्रमुख परिणाम

संसदीय वित्त स्थायी समिति के लिए एक ज्ञापन तैयार किया गया, जिसमें एमएसएमई से जुड़ी प्रमुख चिंताओं जैसे एसएमए (SMA) ढांचे की जटिलताओं, बैंक ऋण रेटिंग (BLR), बैंक शिकायत निवारण तंत्र की चुनौतियों, तथा ऋण पूर्वभुगतान/फोरक्लोज़र शुल्कों से संबंधित मुद्दों को उठाया गया। फोरम ने बड़े कच्चा माल उत्पादकों और एमएसएमई के हितों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पर भी विचार-विमर्श किया।





Key Initiatives in 2024-25(1/2) 2024–25 में प्रमुख पहलें(1/2)



Workshop on Strategic Partnership & Business Opportunities for SMEs: FISME the secretariat for forum in collaboration with IFCI, jointly conducted the workshop. It served as an outreach initiative for the Centre of Excellence for Aspiring SMEs. Shri Rajendra Agrawal, Convenor delivered the valedictory address.

National Roundtable of MSMEs' Access to Finance & Timely Payments: FISME in collaboration with the Global Alliance for Mass Entrepreneurship (GAME), jointly organized the National Roundtable. It focused on key challenges faced by MSMEs related to access to formal credit and delays in payments.

International Conference: FISME organized an International Conference on 'Strategies for Mass Scale Technological Upgradation for MSMEs'. Shri Rajendra Agrawal emphasized importance of policy interventions to support technology adoption by MSMEs.

Discussion on US Reciprocal Tariff: Roundtable examined the impact of reciprocal tariffs on MSMEs. Experts concluded that while reciprocal tariffs are not WTO-friendly, they provide an opportunity for economic restructuring for India. Bilateral Trade Agreements (BTAs) were identified as a practical solution.





एसएमई के लिए रणनीतिक साझेदारी एवं व्यावसायिक अवसरों पर कार्यशाला: फोरम के सचिवालय FISME ने IFCI के सहयोग से इस कार्यशाला का संयुक्त रूप से आयोजन किया। यह कार्यक्रम CoEAS के लिए एक जन-जागरूकता एवं संपर्क पहल के रूप में आयोजित किया गया। फोरम के संयोजक श्री राजेंद्र अग्रवाल ने समापन सत्र को संबोधित किया।

एमएसएमई की वित्त तक पहुंच एवं समय पर भुगतान पर राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन: FISME ने GAME के सहयोग से एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इसमें एमएसएमई के समक्ष औपचारिक ऋण तक पहुंच तथा भुगतान में देरी से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की गई।

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन: FISME ने "एमएसएमई के लिए व्यापक स्तर पर तकनीकी उन्नयन की रणनीतियाँ" विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने एमएसएमई में प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर बल दिया।

अमेरिकी प्रतिशोधात्मक शुल्क पर चर्चा: एमएसएमई पर Reciprocal Tariffs के प्रभाव पर आयोजित चर्चा में विशेषज्ञों ने विचार-विमर्श किया। विशेषज्ञों का मत था कि यद्यपि पारस्परिक शुल्क WTO की भावना के अनुरूप नहीं हैं, फिर भी वे भारत के लिए आर्थिक पुनर्संरचना का अवसर प्रदान करते हैं। इस संदर्भ में BTAs को एक व्यावहारिक समाधान के रूप में रेखांकित किया गया।



Key Initiatives in 2024-25(2/2) 2024-25 में प्रमुख पहलें(2/2)





Discussion on Balancing the Interests of Large Raw Material Producers and MSMEs: The discussion held by the forum highlighted that anti-dumping duties on raw materials increase input costs for MSMEs and reduce their export competitiveness, despite declining global raw material prices. The impact also extends to large manufacturers dependent on MSME supply chains.

बड़े कच्चा माल उत्पादकों एवं एमएसएमई के हितों में संतुलन पर चर्चा: फोरम की चर्चा में बताया गया कि कच्चे माल पर एंटी-डंपिंग शुल्क एमएसएमई की लागत बढ़ाकर उनकी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करते हैं। इसका असर एमएसएमई आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर बड़े विनिर्माण उद्योगों पर पड़ता है।

Major Submissions: (i)Representation before Parliamentary Standing Committee on Finance on issues of access to finance, grievance redressal, foreclosure and prepayment charges and adherence to Code of Bank's Commitment to MSMEs by banks and NBFCs. (ii) Submission before Select Committee of Lok Sabha to Examine the Income Tax Bill 2025, (iii) RBI's Standing Advisory Committee to Review Flow of Credit to MSMEs.

प्रमुख प्रस्तुतियाँ: (i) संसदीय वित्त स्थायी समिति के समक्ष एमएसएमई की वित्त तक पहुंच, शिकायत निवारण, फोरक्लोज़र एवं पूर्वभुगतान शुल्क, तथा बैंकों द्वारा एमएसएमई के प्रति बैंक प्रतिबद्धता संहिता के अनुपालन से संबंधित मुद्दों पर प्रस्तुति दी गई। आयकर विधेयक, 2025 की समीक्षा हेतु गठित लोकसभा की प्रवर समिति तथा (iii) एमएसएमई को ऋण प्रवाह की समीक्षा के लिए आरबीआई की स्थायी सलाहकार समिति के समक्ष भी सुझाव प्रस्तुत किए गए।

Banking Grievance Redressal Portal for MSMEs: With The support of forum, a dedicated online platform designed to address the banking-related concerns and grievances of MSMEs in India was launched. The portal played an important role in reversing foreclosure and pre-payment charges levied by banks.

एमएसएमई हेतु बैंकिंग शिकायत निवारण पोर्टल: फोरम के सहयोग से एमएसएमई की बैंकिंग संबंधी शिकायतों एवं समस्याओं के समाधान के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया। इस पोर्टल ने बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले फोरक्लोज़र एवं पूर्वभुगतान शुल्कों को वापस कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Impact: Notable impacts included Budget announcements for sick industrial units and alternative loan rating mechanisms, SIDBI's direct lending to MSMEs, and a revised MSME classification. Forum's inputs contributed to significant studies which were disseminated to Ministries, PMO, and NITI Aayog.

प्रभाव: फोरम के प्रयासों के परिणामस्वरूप बीमार औद्योगिक इकाइयों तथा वैकल्पिक ऋण रेटिंग तंत्र से संबंधित बजटीय घोषणाएँ हुईं। SIDBI द्वारा एमएसएमई को प्रत्यक्ष ऋण उपलब्ध कराने तथा एमएसएमई वर्गीकरण में संशोधन जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। फोरम के सुझावों पर आधारित अध्ययन तैयार किए गए, जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों, प्रधानमंत्री कार्यालय और नीति आयोग के साथ साझा किया गया।

9th SAMWAD

9वां संवाद



Tradition of organizing dialogues and deliberations between industry representatives and members of 'Friends of MSMEs in Parliament' continued in FY 2025-26 as well. Besides the old members, several new MPs participated in SAMWAD in 2025-26. Th 9th SAMWAD was held on 31st July 2025 in New Delhi.

Key Takeaways: A major breakthrough was achieved when with the support of the forum, an opportunity was secured to make a presentation before the Parliamentary Standing Committee on Finance. This engagement provided a significant platform to present key concerns, relating to SMA Framework leading to premature closures of MSMEs, Bank Loan ratings (BLR) leading to higher interest rates and additional collateral requirements for MSME buyers, lack of grievance redressal for unethical practices of banks such as levying prepayment charges, Rampant misuse of CIBIL reporting and lack of remedial measures. Other areas discussed focussed on Impact of QCOs on MSME manufacturers, obstacles in Ease of Doing Business which include procedural difficulties in GST, regulations related to Fire, Pollution control.

उद्योग प्रतिनिधियों और 'Friends of MSMEs in Parliament' के सदस्यों के बीच संवाद और विचार-विमर्श आयोजित करने की परंपरा वित्त वर्ष 2025-26 में भी जारी रही। पुराने सदस्यों के अलावा, कई नए सांसदों ने 2025-26 में संवाद में भाग लिया। 9वां संवाद 31 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

मुख्य निष्कर्ष: फोरम की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि संसदीय वित्त संबंधी स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुति का अवसर प्राप्त करना रही। इस मंच के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे समिति के समक्ष रखे गए, जिनमें SMA ढांचे के कारण इकाइयों के समयपूर्व बंद होने की समस्या, BLR के चलते ऊंची ब्याज दरों और कोलेटरल की बाध्यता, बैंकों द्वारा प्री-पेमेंट शुल्क जैसी अनैतिक प्रथाओं के विरुद्ध प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र का अभाव तथा CIBIL रिपोर्टिंग के दुरुपयोग और सुधारात्मक उपायों की कमी शामिल थे। समिति ने इन विषयों पर फोरम द्वारा प्रस्तुत सुझावों को गंभीरता से संज्ञान में लिया। इसके अतिरिक्त, QCOs के एमएसएमई विनिर्माताओं पर प्रभाव, जीएसटी अनुपालन, अग्नि सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण तथा बढ़ते नियामकीय अनुपालन बोझ से जुड़ी व्यापार सुगमता संबंधी चुनौतियों को भी उठाया गया।





10th SAMWAD

10वाँ संवाद





Key Submissions and Suggestions

Suggestions for Labour Codes: Involvement of Industry Associations in facilitation-based compliance framework to enhance compliance awareness and reduce burden on MSMEs. With digital submission replacing old ER-I/ER-II forms, vacancy and employment data reporting to employment exchanges should be made optional

Submissions for Union Budget 2026-27: Implementation of an ECLGS-style support for impacted exporters, Adoption of Self-Certification Model or with third-party certifications. Expansion of adoption of Insurance Surety by developing an MSME rating model in consultation with stakeholders

Suggestions for Next Generation Reforms: Single social security charge on enterprises; implementation by govt, expanding coverage of IBC on individual and self-employed (partnership and firms), Reforming urban development framework legalizing working from home.

Income Tax Related Suggestions: The tax-free conversion limit from Company to LLP should be raised to align with MSMED Act thresholds for MSEs. SME companies should be allowed tax-free conversion to LLPs.

IBC Amendment Bill: The Forum facilitated a presentation before the Select Committee examining the IBC. MSME concerns were taken note of by the Committee

प्रमुख प्रस्तुतियाँ एवं सुझाव

Labour Codes हेतु सुझाव: अनुपालन जागरूकता बढ़ाने और MSMEs पर अनुपालन बोझ कम करने के लिए उद्योग संघों को सुविधा-आधारित अनुपालन व्यवस्था में शामिल किया जाए। ER-I/ER-II प्रपत्रों के स्थान पर डिजिटल प्रणाली लागू होने के बाद Employment Exchange को रिक्तियों एवं रोजगार संबंधी जानकारी देना वैकल्पिक किया जाए।

केंद्रीय बजट 2026-27 हेतु सुझाव: प्रभावित निर्यातकों के लिए ECLGS जैसी सहायता योजना लागू की जाए। स्व-प्रमाणन (Self-Certification) या तृतीय-पक्ष प्रमाणन मॉडल अपनाया जाए। हितधारकों के परामर्श से MSME रेटिंग मॉडल विकसित कर Insurance Surety के उपयोग का विस्तार किया जाए।

अगली पीढ़ी के सुधार (Next Generation Reforms): उद्यमों के लिए एकल सामाजिक सुरक्षा शुल्क लागू किया जाए, जिसका क्रियान्वयन सरकार द्वारा किया जाए। IBC का दायरा व्यक्तिगत एवं स्व-रोज़गार (फर्म/साझेदारी) इकाइयों तक बढ़ाया जाए। घर से काम को वैध बनाने हेतु शहरी विकास ढांचे में सुधार किए जाएं।

आयकर संबंधी सुझाव: कंपनी से LLP में कर-मुक्त रूपांतरण की सीमा MSMED अधिनियम के MSE मानकों के अनुरूप बढ़ाई जाए। SME कंपनियों को LLP में कर-मुक्त रूपांतरण की अनुमति दी जाए।

आईबीसी संशोधन विधेयक: फोरम ने आईबीसी की समीक्षा कर रही प्रवर समिति के समक्ष एक प्रस्तुति का आयोजन कराया। समिति ने एमएसएमई क्षेत्र की चिंताओं पर संज्ञान लिया।

11th SAMWAD

11वां संवाद





Key Discussion Points

Union Budget 2026-27: MoMSME budget allocation remains steady at ~₹24,566 crore, though only around 50% of the Revised Estimates have been utilized. Key concerns include limited absorptive capacity and an increasing reliance on credit-based interventions, while critical areas such as technology upgradation and strengthening access to justice remain inadequately addressed. long-pending FISME recommendation to revise CSR applicability thresholds still to be considered.

Long term intervention: Cities as engines of growth: A stronger policy focus on Tier-II and Tier-III cities is needed by identifying and developing City Economic Regions (CERs) based on their unique position as economic growth drivers. This reform-cum-results financing framework aligns with the broader emphasis on regional economic development highlighted in the Economic Survey, Union Budget, and Finance Commission recommendations.

Release of Report- "Making Digital Advertising Work for MSMEs": The report was released in the esteemed presence of members of forum. The study highlights significant challenges faced by MSMEs in digital advertising, including limited visibility of returns on investment (ROI), transparency and measurement gaps, and low diversification of advertising channels.

मुख्य चर्चा बिंदु

केंद्रीय बजट 2026-27: MSME मंत्रालय का बजट आवंटन लगभग ₹24,566 करोड़ पर स्थिर है, परंतु संशोधित अनुमान (RE) का केवल लगभग 50% ही व्यय हो पाया है। प्रमुख चिंताओं में सीमित व्यय क्षमता तथा ऋण-आधारित योजनाओं पर बढ़ती निर्भरता शामिल है, जबकि प्रौद्योगिकी उन्नयन और न्याय तक पहुंच को सुदृढ़ करने जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। CSR पात्रता सीमा में संशोधन संबंधी FISME की लंबित सिफारिशों पर भी अभी निर्णय अपेक्षित है।

दीर्घकालिक हस्तक्षेप: आर्थिक विकास के प्रेरक के रूप में शहर: टियर-II और टियर-III शहरों की विशिष्ट विकास क्षमताओं के आधार पर CERs की पहचान और विकास हेतु अधिक सशक्त नीतिगत ध्यान आवश्यक है। यह सुधार-आधारित परिणाम वित्तपोषण ढाँचा आर्थिक सर्वेक्षण, केंद्रीय बजट और वित्त आयोग द्वारा रेखांकित क्षेत्रीय आर्थिक विकास के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

रिपोर्ट विमोचन – "एमएसएमई के लिए डिजिटल विज्ञापन को प्रभावी बनाना": यह रिपोर्ट मंच के सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति में जारी की गई। अध्ययन में डिजिटल विज्ञापन के क्षेत्र में एमएसएमई द्वारा सामना की जा रही प्रमुख चुनौतियों को रेखांकित किया गया है, जिनमें निवेश पर प्रतिफल (ROI) की सीमित दृश्यता, पारदर्शिता एवं मापन संबंधी कमियाँ, तथा विज्ञापन माध्यमों का सीमित विविधीकरण शामिल हैं।

Workshop on Maximizing Returns from Digital Advertising for MSMEs

एमएसएमई के लिए डिजिटल विज्ञापन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने पर कार्यशाला



FISME, secretariat to 'Friends of MSMEs in Parliament' hosted a workshop on 9th July 2025 in New Delhi, focusing on improving transparency, data reliability, and return on investment (ROI) in digital advertising for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The workshop underscored a clear message from MSMEs: greater capacity building, and reliable data are essential for digital advertising to truly serve their business goal.

Key issues discussed during the workshop included opaque pricing structures, limited access to performance tracking tools, and the absence of standardised ad measurement systems. Industry experts stressed the importance of independent audience measurement to foster transparency and build trust among MSME advertisers.

The workshop concluded with a unified call for greater industry collaboration, transparent market practices, and focused capacity-building efforts to enable MSMEs to harness the full potential of digital advertising in India's expanding digital economy. Findings and recommendations of study were compiled in a study titled- 'Making Digital Advertising Work for MSMEs', which was released by 'Friends of MSMEs in Parliament' at the 11th SAMWAD dialogue held in New Delhi.

''फ्रेंड्स ऑफ MSMEs इन पार्लियामेंट' के सचिवालय FISME ने 9 जुलाई 2025 को नई दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए डिजिटल विज्ञापन में पारदर्शिता, विश्वसनीय डेटा और निवेश पर प्रतिफल (ROI) बढ़ाने पर चर्चा हुई। MSME प्रतिनिधियों ने क्षमता निर्माण और भरोसेमंद डेटा को डिजिटल विज्ञापन की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक बताया।

कार्यशाला में अपारदर्शी मूल्य निर्धारण, प्रदर्शन ट्रैकिंग टूल्स तक सीमित पहुंच तथा विज्ञापन मापन के मानकीकृत तंत्र के अभाव जैसे मुद्दे उठाए गए। विशेषज्ञों ने पारदर्शिता और विश्वास बढ़ाने हेतु स्वतंत्र ऑडियंस मापन प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यशाला का समापन उद्योग सहयोग, पारदर्शी बाजार प्रथाओं और MSMEs के लिए लक्षित क्षमता निर्माण की सामूहिक मांग के साथ हुआ, ताकि वे भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में डिजिटल विज्ञापन का पूरा लाभ उठा सकें। कार्यशाला के निष्कर्ष एवं सुझावों को 'Making Digital Advertising Work for MSMEs' शीर्षक अध्ययन में संकलित किया गया, जिसका विमोचन 'फ्रेंड्स ऑफ MSMEs इन पार्लियामेंट' के सदस्यों द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 11वें 'संवाद' कार्यक्रम में किया गया।

National Conference For MSMEs

एमएसएमई हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन





'Friends of MSMEs in Parliament' and FISME, its secretariat, jointly organised the National Conference on "Strengthening the Legal and Regulatory Architecture for Growth of MSMEs" on 6th January 2026 in New Delhi. The conference was inaugurated by Ms. Shobha Karandlaje, Hon'ble Minister of State, Ministry of MSME, Government of India, as Chief Guest. In her keynote address, she emphasised the need for skilling, technology upgradation, and making the banking system more MSME-friendly, highlighting ongoing discussions with the Ministry of Finance.

Three thematic sessions deliberated on MSME laws and regulations, Delivery of justice, and MSME finance, chaired by Shri Sujeet Kumar, MP and Mr. Neeraj Kedia, Chairman, Banking and Finance Committee, FISME. Shri Rajendra Agrawal, Convenor, in his inaugural address stressed on the need to build a transparent, resilient and future ready MSME ecosystem. Three thematic sessions deliberated on MSME laws and regulations, Delivery of justice, and finance.

'Friends of MSMEs in Parliament' तथा उसके सचिवालय फिस्मे (FISME) ने संयुक्त रूप से 6 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में "एमएसएमई की वृद्धि हेतु कानूनी एवं नियामकीय ढाँचे को सुदृढ़ बनाना" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री Shobha Karandlaje ने किया। अपने मुख्य संबोधन में उन्होंने कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा बैंकिंग प्रणाली को अधिक एमएसएमई-अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया

उन्होंने इस संबंध में वित्त मंत्रालय के साथ चल रही चर्चाओं का उल्लेख किया। उद्घाटन सत्र में श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने एक पारदर्शी, सुदृढ़ एवं भविष्य के लिए तैयार एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया।सम्मेलन के अंतर्गत तीन विषयगत सत्र आयोजित किए गए, जिनमें एमएसएमई कानून एवं विनियम, न्याय प्रदान करने की व्यवस्था तथा एमएसएमई वित्तपोषण से संबंधित मुद्दों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ।





Initiative Skill Development in Meerut

मेरठ में कौशल विकास की पहल



A roundtable discussion titled 'Increasing Uptake of Skill Development in Meerut' was held in Meerut, bringing together policymakers, industry representatives, and civil society organisations to enhance skill development adoption. Special guests included Chief Guest Shri Kapil Dev Aggarwal, Minister of State (Independent Charge), Vocational Education and Skill Development, Uttar Pradesh; Shri Rajendra Agrawal, former MP, Meerut and Convenor of 'Friends of MSMEs in Parliament'; and Shri Amit Agarwal, MLA, Meerut Cantonment.

The discussion focused on building a positive societal perception of skilling and enabling students to make informed choices. It highlighted that India has largely prioritised training youth under existing schemes, rather than empowering them to choose pathways based on aspiration, earning potential, dignity, and mobility.

Shri Kapil Dev Aggarwal announced full government support for organising a 'Pilot Skill and Career Counselling Fair' in Meerut. Shri Rajendra Agrawal suggested conducting a comprehensive census in every district to accurately identify the specific skills. Shri Amit Aggarwal stressed the need to foster a sense of dignity around ITIs and vocational courses.

मेरठ में 'कौशल विकास को बढ़ावा' विषय पर एक गोलमेज चर्चा आयोजित की गई, जिसमें नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने कौशल विकास की पहुँच और प्रभाव बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व सांसद एवं 'फ्रेंड्स ऑफ MSMEs इन पार्लियामेंट' के संयोजक श्री राजेन्द्र अग्रवाल, तथा मेरठ कैंट के विधायक श्री अमित अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

चर्चा का केंद्र कौशल विकास के प्रति सकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा युवाओं को उनकी आकांक्षाओं, आय की संभावनाओं और सम्मानजनक रोजगार के आधार पर सूचित करियर विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाना रहा।

इस अवसर पर श्री कपिल देव अग्रवाल ने मेरठ में 'पायलट स्किल एवं करियर काउंसलिंग मेले' के आयोजन हेतु राज्य सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने औद्योगिक क्लस्टरों की कौशल आवश्यकताओं के आकलन के लिए प्रत्येक जिले में व्यापक सर्वेक्षण कराने का सुझाव दिया, जबकि श्री अमित अग्रवाल ने आईटीआई एवं अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के प्रति सम्मान और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने पर बल दिया।

Forum Hosts Google Delegation

फोरम द्वारा गूगल प्रतिनिधिमंडल का स्वागत



On May 8, 2026, the Friends of MSMEs in Parliament hosted a high-level Google delegation in New Delhi to explore collaborative opportunities for strengthening India's Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector. The discussions focused on leveraging Google's digital tools and platforms to enhance MSME competitiveness, accelerate digital transformation, and improve access to domestic and global markets.

During the meeting, Members of Parliament and representatives from the Federation of Indian Micro and Small & Medium Enterprises (FISME) shared the ground-level challenges faced by small businesses. They highlighted issues such as limited digital infrastructure, financial constraints, low digital awareness, and barriers to technology adoption, emphasizing the need for targeted support to enable wider digital inclusion.

Recognizing the importance of public-private collaboration, the stakeholders expressed interest in partnering with Google to develop scalable support programmes for MSMEs. The proposed initiatives included technology adoption, market access, and capacity-building efforts aimed at bridging the digital divide.

8 मई, 2026 को Friends of MSMEs in Parliament ने नई दिल्ली में गूगल के एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी की। इस बैठक का उद्देश्य भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर विचार-विमर्श करना था। चर्चा का मुख्य केंद्र गूगल के डिजिटल टूल्स और प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने, डिजिटल परिवर्तन को गति देने तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों तक बेहतर पहुँच प्रदान करने पर रहा।

बैठक के दौरान सांसदों तथा FISME के प्रतिनिधियों ने एमएसएमई क्षेत्र की जमीनी चुनौतियों से अवगत कराया। उन्होंने सीमित डिजिटल अवसंरचना, वित्तीय बाधाओं, डिजिटल जागरूकता की कमी तथा नई तकनीकों को अपनाने में आने वाली कठिनाइयों जैसे प्रमुख मुद्दों को रेखांकित करते हुए व्यापक डिजिटल समावेशन के लिए लक्षित सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी के महत्व को स्वीकार करते हुए सभी हितधारकों ने एमएसएमई के लिए अनुकूलित एवं व्यापक स्तर पर लागू किए जा सकने वाले सहयोग कार्यक्रम विकसित करने हेतु गूगल के साथ रणनीतिक साझेदारी में रुचि व्यक्त की।

Roundtable on Digital Interoperability

डिजिटल इंटरऑपरेबिलिटी पर चर्चा



Digital technologies are rapidly reshaping how businesses produce, sell, comply, and compete. MSMEs adoption of technology very differently from large firms. Operating under tight financial and managerial constraints, they adopt tools incrementally and reactively often in response to regulatory mandates, platform requirements, or customer expectations. Over time, this leads to a fragmented mix of devices and software sourced from multiple vendors, frequently built on incompatible and proprietary platforms. From an MSMEs' perspective, the lack of interoperability has become a silent but serious barrier to competitiveness. Adoption of technology has become important for MSMEs to remain competitive, sustain their operations and grow. Interoperability in manufacturing means the ability to use different industrial systems to connect and communicate seamlessly in all production areas.

डिजिटल प्रौद्योगिकियां व्यवसायों के उत्पादन, विपणन, अनुपालन और प्रतिस्पर्धा के तरीकों को तेजी से बदल रही हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में MSMEs सीमित वित्तीय एवं प्रबंधकीय संसाधनों के कारण तकनीक को चरणबद्ध और आवश्यकता-आधारित तरीके से अपनाते हैं। परिणामस्वरूप, उनके पास विभिन्न विक्रेताओं से प्राप्त और अक्सर असंगत प्लेटफॉर्मों पर आधारित उपकरणों एवं सॉफ्टवेयर का बिखरा हुआ तंत्र विकसित हो जाता है। MSMEs के लिए इंटरऑपरेबिलिटी (परस्पर कार्य-संगतता) की कमी प्रतिस्पर्धात्मकता में एक महत्वपूर्ण बाधा बन गई है। प्रतिस्पर्धी बने रहने, संचालन को सुचारू रखने और विकास के लिए तकनीक अपनाना आवश्यक है। विनिर्माण क्षेत्र में इंटरऑपरेबिलिटी का अर्थ है विभिन्न औद्योगिक प्रणालियों का उत्पादन प्रक्रिया के सभी चरणों में निर्बाध रूप से जुड़ना और संवाद करना।

To deliberate on the above issues, 'Friends of MSMEs in Parliament' and its secretariat FISME organized a Roundtable on MSME Competitiveness & Digital Interoperability on 12 February 2026 in New Delhi.

इन्हीं मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए 'फ्रेंड्स ऑफ MSMEs इन पार्लियामेंट' और उसके सचिवालय FISME ने 12 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में "MSME प्रतिस्पर्धात्मकता एवं डिजिटल इंटरऑपरेबिलिटी" विषय पर एक गोलमेज बैठक आयोजित की।





Interaction With IIT-M Delegation

आईआईटी-मद्रास प्रतिनिधिमंडल के साथ संवाद





Friends of MSMEs in Parliament and FISME hosted a 60-member delegation from the Public Policy Group of IIT Madras on 18th December 2025 in New Delhi.

The programme was chaired by Shri Shankar Lalwani, Hon'ble Member of Parliament and Chairman of Friends of MSMEs in Parliament, Shri Rajendra Agrawal, Convenor and Core Committee Member of Friends of MSMEs in Parliament, Shri Sujeet Kumar, Member of Parliament (RS) were also present.

The delegation was welcomed by Shri S.K. Jain, President of FISME, Shri Rakesh Chhabra, Vice President and Shri Dinesh Singhal, Past President of FISME were also in attendance. The meeting ensued engaging discussions between the students and faculty members of IIT Madras and the leadership of Friends of MSMEs in Parliament.

18 दिसंबर 2025 को, फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट और FISME ने नई दिल्ली में आईआईटी मद्रास के पब्लिक पॉलिसी ग्रुप के 60-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की मेज़बानी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंच के अध्यक्ष एवं माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी ने की।

फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट के संयोजक एवं कोर कमेटी सदस्य श्री राजेन्द्र अग्रवाल तथा राज्यसभा सांसद श्री सुजीत कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत FISME के अध्यक्ष श्री एस.के. जैन ने किया। FISME के उपाध्यक्ष श्री राकेश छाबड़ा तथा पूर्व अध्यक्ष श्री दिनेश सिंघल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

बैठक के दौरान आईआईटी मद्रास के छात्रों एवं संकाय सदस्यों तथा फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ in पार्लियामेंट के नेतृत्व के बीच विभिन्न नीतिगत एवं एमएसएमई-संबंधी विषयों पर सार्थक और विचारोत्तेजक चर्चा हुई।





Representation to Government (1/3)

सरकार के समक्ष सुझाव (1/3)





Nomination of FISME to UP Govt. Economic Advisory Group: The Uttar Pradesh government has announced the formation of a new Economic Advisory Group (EAG) designed to provide independent and specialized economic counsel on various economic and policy matters. The advisory body, constituted to help the state make informed long-term strategic decisions, will focus on evaluating governmental programs and policies while promoting economic stability, inclusive development, and fiscal discipline. FISME, secretariat for 'Friends of MSMEs in Parliament' is also represented in the group as a member. The EAG will serve as a bridge between government departments and domain experts, fostering collaboration between policymakers, economists, business leaders, and academic institutions. The EAG has been tasked with providing independent inputs to the Uttar Pradesh Government on key economic issues.

Submission before Chief Economic Advisor: FISME, in a meeting with the Chief Economic Advisor, Mr. V Nageswaran, outlined several key recommendations to address the impact of increasing protectionist measures on the sector. FISME called for immediate government intervention following the recent HSBC India Manufacturing Purchasing Manager's Index (PMI) report, which revealed manufacturing activity has hit a 12-month low. It also advocated for the formation of a group of ministers to oversee these measures. expressed particular concern over recent QCOs in the steel sector, which have introduced 151 rigorous standards that effectively restrict imports. In deliberations held with 'Friends of MSMEs in Parliament', it was emphasized that the decline in MSME competitiveness due to higher input costs and reduced market access will lead to job losses within the sector.

उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक सलाहकार समूह (EAG) में FISME का नामांकन: उत्तर प्रदेश सरकार ने विभिन्न आर्थिक एवं नीतिगत विषयों पर स्वतंत्र और विशेषज्ञ आर्थिक सलाह प्रदान करने के लिए एक नए आर्थिक सलाहकार समूह (EAG) के गठन की घोषणा की है। राज्य को दीर्घकालिक रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता हेतु गठित यह समूह सरकारी कार्यक्रमों एवं नीतियों के मूल्यांकन के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता, समावेशी विकास और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहेगा। 'फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट' के सचिवालय के रूप में FISME को भी इस समूह में सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। EAG सरकार के विभागों और विषय-विशेषज्ञों के बीच सेतु का कार्य करते हुए नीति-निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों, उद्योग जगत के नेताओं और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा तथा प्रमुख आर्थिक मुद्दों पर उत्तर प्रदेश सरकार को स्वतंत्र सुझाव प्रदान करेगा।

मुख्य आर्थिक सलाहकार के समक्ष प्रस्तुति: FISME ने मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री वी. नागेश्वरन के साथ बैठक में बढ़ते संरक्षणवादी उपायों के एमएसएमई क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। संगठन ने एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई रिपोर्ट में विनिर्माण गतिविधियों के 12 माह के निचले स्तर पर पहुंचने के मद्देनज़र तत्काल सरकारी हस्तक्षेप तथा इन उपायों की निगरानी के लिए मंत्रियों के एक समूह के गठन की मांग की। FISME ने इस्पात क्षेत्र में हाल ही में लागू किए गए 151 कड़े QCO मानकों पर भी चिंता व्यक्त की, जो आयात को प्रभावी रूप से सीमित करते हैं। 'फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट' के साथ हुई चर्चाओं में यह रेखांकित किया गया कि बढ़ती लागत और बाजार पहुंच में कमी के कारण एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता घटेगी, जिससे रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

Representation to Government (2/3)

सरकार के समक्ष सुझाव (2/3)



Submissions for Union Budget 2026-27: Key recommendations for the budget were presented by FISME, secretariat for the forum. These recommendations focused on improving finance, exports, quality compliance, public procurement, technology adoption, and taxation for MSMEs. These included introducing ECLGS-style financial support for affected exporters, reforming the QCO regime through self-certification and a compliance-based approach, expanding the use of insurance surety and institutional arbitration in public procurement, establishing a National Technology Upgradation Mission, and rationalizing tax provisions by raising the tax-free company-to-LLP conversion limit and allowing SME companies a limited-term tax-free conversion to LLPs.

Submission before Conclave on Pan-India Horizontal Audit on Ease of Doing Business for MSMEs by CAG: Submission by FISME at the conclave highlighted that improving the ease of doing business for MSMEs requires going beyond registration to address compliance costs, infrastructure gaps, regulatory predictability, technology outcomes, and access to finance. FISME emphasized the need for outcome-based policies, smoother business exit mechanisms, and better oversight of inspections and banking practices. It was also suggested that AI-driven integration of datasets such as GST, Udyam, banking, inspection, and court records could enable continuous, impact-focused policy evaluation rather than traditional expenditure-based audits.



केंद्रीय बजट 2026-27 हेतु प्रस्तुतियाँ: फोरम के सचिवालय के रूप में FISME ने बजट के लिए प्रमुख सिफारिशें प्रस्तुत कीं। ये सिफारिशें एमएसएमई क्षेत्र में वित्त, निर्यात, गुणवत्ता अनुपालन, सार्वजनिक खरीद, प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा कराधान से संबंधित सुधारों पर केंद्रित थीं। इनमें प्रभावित निर्यातकों के लिए ECLGS जैसी वित्तीय सहायता व्यवस्था लागू करना, स्व-प्रमाणीकरण एवं अनुपालन-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से QCO व्यवस्था में सुधार करना, सार्वजनिक खरीद में बीमा-आधारित श्योरिटी तथा Institutional Arbitration के उपयोग का विस्तार करना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उन्नयन मिशन की स्थापना करना, तथा कंपनी से LLP में कर-मुक्त रूपांतरण की सीमा बढ़ाने और एसएमई कंपनियों को सीमित अवधि के लिए कर-मुक्त रूप से एलएलपी में परिवर्तित होने की अनुमति देकर कर प्रावधानों को अधिक तर्कसंगत बनाना शामिल था।

MSMEs के लिए कारोबार सुगमता पर सीएजी के अखिल भारतीय क्षैतिज Horizontal Audit संबंधी कॉन्क्लेव के समक्ष प्रस्तुति: कॉन्क्लेव में FISME ने कहा कि एमएसएमई के लिए कारोबार सुगमता केवल पंजीकरण तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि अनुपालन लागत, आधारभूत संरचना, नियामकीय पूर्वानुमेयता, तकनीकी प्रभाव और वित्त तक पहुंच जैसी चुनौतियों का समाधान भी आवश्यक है। संगठन ने परिणाम-आधारित नीतियों, सरल व्यवसाय-समापन व्यवस्था तथा निरीक्षण और बैंकिंग प्रक्रियाओं की बेहतर निगरानी पर जोर दिया। साथ ही, जीएसटी, उद्यम, बैंकिंग, निरीक्षण और न्यायालय संबंधी आंकड़ों के एआई-संचालित एकीकरण के माध्यम से निरंतर और प्रभाव-केंद्रित नीति मूल्यांकन का सुझाव दिया गया।

Representation to Government (3/3)

सरकार के समक्ष सुझाव (3/3)





Letter to Hon'ble Prime Minister: Friends of MSMEs in Parliament, after consultations with MSME associations, welcomed the Union Budget 2026–27 for addressing key sectoral challenges through measures to improve credit access, technology adoption, productivity, skilling, and ease of doing business. In a letter to the Hon'ble Prime Minister, the forum particularly appreciated the transformation of 200 MSME clusters and the focus on Tier-II and Tier-III cities, describing them as important steps toward balanced regional development, job creation, and MSME-led inclusive growth. It also highlighted the role of post-budget sectoral webinars in accelerating implementation.

माननीय प्रधानमंत्री को पत्र: फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट ने एमएसएमई संघों से परामर्श के बाद, ऋण उपलब्धता, प्रौद्योगिकी अपनाने, उत्पादकता, कौशल विकास और कारोबार सुगमता में सुधार संबंधी प्रावधानों के माध्यम से क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों के समाधान हेतु केंद्रीय बजट 2026–27 का स्वागत किया। माननीय प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में फोरम ने 200 एमएसएमई क्लस्टरों के रूपांतरण तथा टियर-II और टियर-III शहरों पर विशेष ध्यान को संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार सृजन और एमएसएमई-आधारित समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। बजटोत्तर क्षेत्रीय वेबिनारों की भूमिका को क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए महत्वपूर्ण बताया गया।

Submission before Board of Trade, Ministry of Commerce and Industry: FISME, secretariat for 'Friends of MSMEs in Parliament' put forth trade related issues of MSMEs before the Board of Trade meeting and proposed for creation of India International Trading Companies (IITCs) to address the structural constraints faced by MSMEs in global markets. Proposal aims to promote private sector-led export development and significantly expand MSME participation in global trade.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के व्यापार बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति: फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट के सचिवालय के रूप में FISME ने व्यापार बोर्ड की बैठक में एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े व्यापारिक मुद्दे उठाए और वैश्विक बाजारों में एमएसएमई के समक्ष मौजूद संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनियों (IITCs) के गठन का प्रस्ताव रखा। इस पहल का उद्देश्य निजी क्षेत्र-नेतृत्व वाले निर्यात विकास को बढ़ावा देना तथा वैश्विक व्यापार में एमएसएमई की भागीदारी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाना है।

SubmissionBeforeLokSabhaSelectCommitteeonIBC (Amendment Bill, 2025): FISME made presentation before the committee. Recommendations focussed on incorporating specific safeguards to ensure both equity and effectiveness for MSMEs, including formal representation in resolution processes, priority in the recovery of dues, prescription of a minimum recovery threshold 5% for MSME dues within the asset distribution mechanism under Section 53 of IBC.

लोकसभा की आईबीसी (संशोधन) विधेयक, 2025 संबंधी प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुति: FISME ने समिति के समक्ष एमएसएमई हितों की सुरक्षा हेतु सुझाव प्रस्तुत किए, जिनमें समाधान प्रक्रिया में उनका औपचारिक प्रतिनिधित्व, बकाया राशि की वसूली में प्राथमिकता तथा आईबीसी की धारा 53 के तहत परिसंपत्ति वितरण में एमएसएमई देयों के लिए न्यूनतम 5% वसूली सीमा निर्धारित करने की सिफारिश शामिल थी।

Research Studies

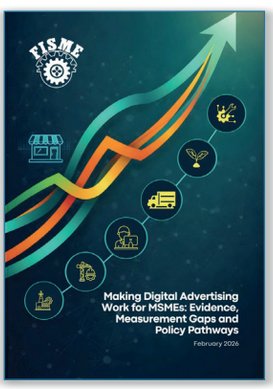
शोध कार्य





'Making Digital Advertising Work for MSMEs': To address the limited research on MSMEs' digital advertising choices, FISME surveyed 300 MSMEs to identify key constraints affecting advertising decisions. The study found that poor ROI visibility, along with transparency and measurement gaps, significantly undermines advertising effectiveness. It recommends a legal framework mandating independent audience measurement and verification. The report was released during the 11th SAMWAD in the presence of distinguished forum members.

'Report on MSMEs Access to Finance and Timely Payments': The report, launched in November 2025 in the presence of Chief Economic Advisor Dr. V. Anantha Nageswaran and DPIIT Additional Secretary Ateesh Kumar Singh, noted that delayed MSME receivables declined to ₹7.34 lakh crore by March 2024. It recommends stricter enforcement of Section 43Bh of the Income Tax Act, public disclosure of chronic defaulters, expanded use of TReDS through GST and Udyam integration, and stronger Facilitation Councils for quicker dispute resolution. Key issues highlighted—such as the SMA framework, credit access challenges, prolonged litigation, and GST compliance—were discussed during SAMWAD dialogues with Friends of MSMEs in Parliament and presented at relevant forums.



'Making Digital Advertising Work for MSMEs': MSME के डिजिटल विज्ञापन विकल्पों पर सीमित शोध की कमी को दूर करने के लिए, FISME ने 300 एमएसएमई का सर्वेक्षण कर विज्ञापन निर्णयों में आने वाली प्रमुख बाधाओं की पहचान की। अध्ययन में पाया गया कि ROI (निवेश पर प्रतिफल) की कम स्पष्टता तथा पारदर्शिता और मापन संबंधी कमियाँ विज्ञापन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। रिपोर्ट में स्वतंत्र ऑडियंस मापन एवं सत्यापन को अनिवार्य बनाने हेतु कानूनी ढाँचा विकसित करने की सिफारिश की गई है। यह रिपोर्ट SAMWAD के दौरान सदस्यों की उपस्थिति में जारी की गई।

'Report on MSMEs Access to Finance and Timely Payments': नवंबर 2025 में मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन और DPIIT के अतिरिक्त सचिव अतीश कुमार सिंह की उपस्थिति में जारी इस रिपोर्ट में बताया गया कि मार्च 2024 तक एमएसएमई की बकाया देय राशि घटकर ₹7.34 लाख करोड़ रह गई। रिपोर्ट में आयकर अधिनियम की धारा 43Bh के कड़े अनुपालन, लगातार भुगतान चूक करने वालों के सार्वजनिक प्रकटीकरण, GST एवं उद्यम डेटा के साथ TReDS के व्यापक एकीकरण तथा त्वरित विवाद निपटान हेतु Facilitation Councils को सशक्त बनाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में उठाए गए प्रमुख मुद्दों—जैसे SMA ढाँचा, ऋण तक पहुँच की चुनौतियाँ, लंबित मुकदमों का आर्थिक विकास पर प्रभाव और GST अनुपालन—पर SAMWAD बैठकों तथा अन्य संबंधित मंचों पर चर्चा की गई।



Impact of Initiatives

उपक्रमों का प्रभाव





'Friends of MSMEs in Parliament' and FISME consistently pursued the issue of foreclosure and pre-payment charges on MSME loans at various policy forums. Collated cases of foreclosure and pre-payment charges, received via email, letters and through banking grievance redressal portal. Over 100 cases were reported. The dysfunctional nature of Banking Ombudsman in dealing with MSMEs complaints were also brough to RBI's notice.

A representation was submitted to Shri Bhartruhari Mahtab, Chairman, Parliamentary Standing Committee (Finance), and the matter was also discussed during a meeting of a FISME delegation led by Shri Rajendra Agrawal. The issue was further raised by the FISME President during the pre-budget consultations for Union Budget 2026–27 in December 2025.

As a major outcome, the RBI Directions, 2025 prohibit commercial banks, NBFCs, and other financial institutions from levying pre-payment charges on floating-rate business loans to individuals and MSEs. RBI has further clarified that regulated entities cannot include pre-payment charge clauses in loan documents for eligible MSE floating-rate loans and that the prohibition applies to all MSMEs, irrespective of loan size.

'Friends of MSMEs in Parliament' और FISME ने MSME ऋणों पर फोरक्लोज़र एवं प्री-पेमेंट शुल्क के मुद्दे को लगातार विभिन्न नीति मंचों पर उठाया। ई-मेल, पत्रों तथा बैंकिंग शिकायत निवारण पोर्टल के माध्यम से प्राप्त 100 से अधिक मामलों का संकलन किया गया तथा MSME शिकायतों के निस्तारण में बैंकिंग ओम्बड्समैन की निष्क्रियता को भी RBI के संज्ञान में लाया गया।

इस संबंध में संसदीय स्थायी समिति (वित्त) के अध्यक्ष श्री भर्तृहरि महताब को ज्ञापन सौंपा गया तथा 'Friends of MSMEs in Parliament' के संयोजक श्री राजेन्द्र अग्रवाल के नेतृत्व में FISME प्रतिनिधिमंडल ने समिति के समक्ष यह मुद्दा उठाया। दिसंबर 2025 में केंद्रीय बजट 2026-27 की पूर्व-बजट परामर्श बैठक में भी FISME ने इस विषय को प्रमुखता से रखा।

इसके परिणामस्वरूप RBI के 2025 निर्देशों के तहत बैंकों, NBFCs एवं अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा व्यक्तियों और MSEs को दिए गए फ्लोटिंग रेट व्यवसायिक ऋणों पर प्री-पेमेंट शुल्क लगाने पर रोक लगाई गई। मार्च 2026 में RBI गवर्नर के साथ बैठक में FISME ने इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा, जिस पर RBI ने स्पष्ट किया कि पात्र MSE फ्लोटिंग रेट ऋणों के लिए ऋण दस्तावेजों में प्री-पेमेंट शुल्क का प्रावधान नहीं किया जा सकता तथा यह प्रतिबंध सभी MSMEs पर, ऋण राशि की परवाह किए बिना, लागू होगा।





Interactions With Policy Makers

नीति-निर्माताओं के साथ संवाद





In an effort to inform about the Forum and its objectives, a delegation led by Shri Rajendra Agrawal, Convenor, engaged with key policymakers and parliamentarians. Productive interactions were held with Sushri Shobha Karandlaje, Minister of State, Ministry of MSME; Shri Shashank Mani Tripathi, Hon'ble MP from Deoria (Uttar Pradesh); Smt. Bansuri Swaraj, Hon'ble MP from New Delhi; and Shri Sujeet Kumar, MP (Rajya Sabha) representing Odisha.

फोरम एवं उसके उद्देश्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए फोरम के संयोजक श्री राजेन्द्र अग्रवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख नीति-निर्माताओं एवं सांसदों से संवाद किया। इस क्रम में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, देवरिया (उत्तर प्रदेश) के सांसद श्री शशांक मणि त्रिपाठी, नई दिल्ली की सांसद श्रीमती बांसुरी स्वराज तथा ओडिशा से राज्यसभा सांसद श्री सुजीत कुमार के साथ सार्थक बैठकें आयोजित की गईं।

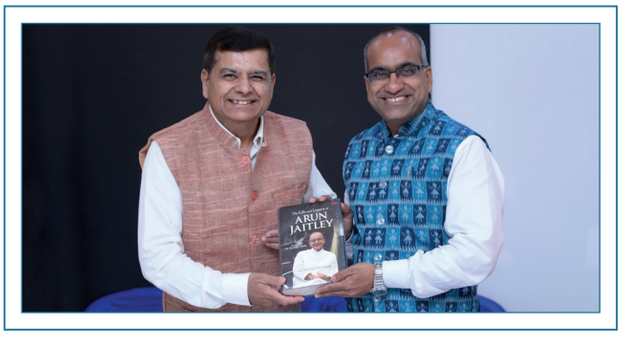
The discussion with Sushri Shobha Karandlaje focussed on the impact of geopolitical crisis in West Asia on MSMEs. In discussion with Shri Shashank Mani Tripathi, findings of Study on Identifying Strategies for Quadrupling Meerut's GDP conducted by FISME were discussed. A similar study is being undertaken for Deoria district, underscoring the importance of district-led economic growth.

सुश्री शोभा करंदलाजे के साथ पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक संकट के MSMEs पर प्रभाव पर चर्चा हुई। वहीं, श्री शशांक मणि त्रिपाठी के साथ FISME द्वारा किए गए मेरठ की जीडीपी को चार गुना बढ़ाने की रणनीतियों संबंधी अध्ययन के निष्कर्ष साझा किए गए। देवरिया जिले में भी इसी प्रकार का अध्ययन किया जा रहा है, जो जिला-आधारित आर्थिक विकास के महत्व को रेखांकित करता है।

Smt. Bansuri Swaraj was briefed about 'Friends of MSMEs in Parliament' Forum and its initiatives. She appreciated the efforts and expressed interest in associating with it. The discussion with Shri Sujeet Kumar focused on the proposed Corporate Laws Amendment Bill and MSME compliance challenges under the Companies Act. He encouraged FISME, as the national body of MSMEs and the forum's secretariat, to present MSME concerns before the Joint Parliamentary Committee (JPC) constituted to examine the Bill.

श्रीमती बांसुरी स्वराज को 'फ्रेंड्स ऑफ MSMEs इन पार्लियामेंट' फोरम एवं उसकी पहलों की जानकारी दी गई। उन्होंने फोरम के प्रयासों की सराहना की और इससे जुड़ने में रुचि व्यक्त की। श्री सुजीत कुमार के साथ प्रस्तावित कॉर्पोरेट कानून संशोधन विधेयक तथा कंपनी अधिनियम के अंतर्गत MSMEs के अनुपालन संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने सुझाव दिया कि MSMEs की राष्ट्रीय संस्था एवं फोरम के सचिवालय के रूप में FISME को इस विधेयक की समीक्षा हेतु गठित संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के समक्ष MSMEs की चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए।





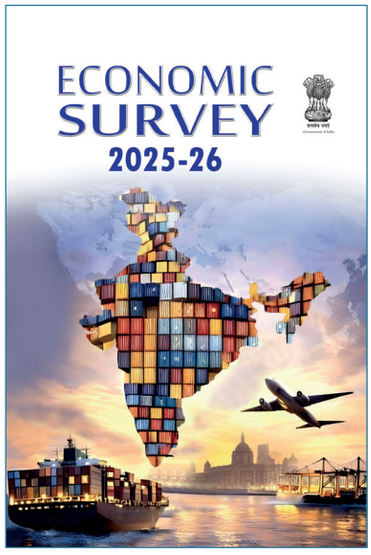
Thematic Focus in 2026-27

2026-27 की विषयगत प्राथमिकताएँ



Tier II and Tier III Cities as drivers of economic growth: Post-Budget Webinar on "Sustaining and Strengthening Economic Growth," by Hon'ble Prime Minister emphasized the need to strengthen industrial clusters and develop Tier-2 and Tier-3 cities as key engines of economic growth. Underscoring the Government's commitment to long-term economic development, hon'ble Prime Minister has stressed for robust infrastructure and efficient logistics to remain core pillars of the nation's growth strategy, enabling greater productivity, connectivity, and investment opportunities across sectors.

Economic Survey's Focus on Planned Urbanization: The Economic Survey emphasizes the importance of planned urbanization, recognizing cities not merely as places of habitation but as critical economic infrastructure that drives growth and development. Survey points out that investment in essential urban infrastructure such as transport, housing, water supply, sanitation, and governance capacity has not kept pace with the rapid expansion of urban areas, creating significant challenges for sustainable urban development.



आर्थिक विकास के प्रेरक के रूप में टियर-II और टियर-III शहर: "सतत एवं सुदृढ़ आर्थिक विकास" विषय पर आयोजित बजट-पश्चात वेबिनार में माननीय प्रधानमंत्री ने औद्योगिक क्लस्टरों को सशक्त बनाने तथा टियर-II और टियर-III शहरों को आर्थिक विकास के प्रमुख इंजन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। दीर्घकालिक आर्थिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर और कुशल लॉजिस्टिक्स देश की विकास रणनीति के मुख्य स्तंभ हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता, और निवेश के अवसरों को बढ़ावा देते हैं।

नियोजित शहरीकरण पर आर्थिक सर्वेक्षण का फोकस: आर्थिक सर्वेक्षण शहरों को केवल रहने के स्थान नहीं, बल्कि आर्थिक विकास को गति देने वाली महत्वपूर्ण आर्थिक अवसंरचना मानता है। सर्वेक्षण के अनुसार, परिवहन, आवास, जलापूर्ति, स्वच्छता तथा शहरी शासन जैसी आवश्यक अवसंरचनाओं में निवेश, शहरी क्षेत्रों के तीव्र विस्तार के अनुरूप नहीं बढ़ पाया है, जिससे सतत शहरी विकास की चुनौतियाँ बढ़ रही हैं।

Forthcoming Initiatives Planned for 2026-27

Roundtables/Conferences with Ministries on Implementing Budget Proposals:

i. **Ministry of Commerce:** On execution of rejuvenation of 200 legacy clusters

ii. **Ministry of Finance and Ministry of MSMEs:** Identifying "Champion MSMEs; Delayed Payment Issues; Mandatory use of TReDS by CPSEs

iii. **Ministry of Urban Development:** Building Tier-2 and Tier-3 cities as engines of economic growth

iv. **Ministry of Law:** National Conference on Economic Tribunals (NCLT, DRT, ITAT, CESTAT etc.)

Participating MPs - 17th and 18th Lok Sabha

17वीं एवं 18वीं लोकसभा के सहभागी सांसद



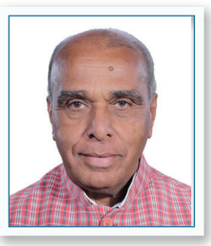
Shri Shankar Lalwani
(Chairman)
Indore, Madhya Pradesh



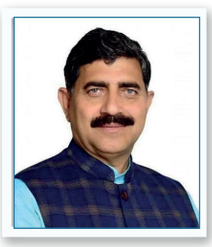
Shri Rajendra Agrawal
(Convenor)
Former MP, Meerut, Uttar Pradesh



Shri Sujeet Kumar
Member Rajya Sabha,
Representing Odisha



Shri Jagdambika Pal
Domariyaganj, Uttar Pradesh



Shri Jugal Kishore
Jammu



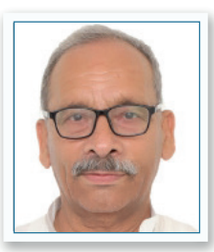
Dr. Sanjay Jaiswal
West Champaran, Bihar



Shri Jagadish Shettar
Belgaum, Karnataka



Shri Shashank Mani Tripathi
Deoria , Uttar Pradesh



Dr. Rajkumar Sangwan
Baghpat, Uttar Pradesh



Shri Naresh Bansal
Member of Rajya Sabha,
Representing Uttarakhand



Shri Sudhir Gupta
Mandaur, Madhya Pradesh



Shri Atul Garg
Ghaziabad (Uttar Pradesh)

Participating MPs - 17th and 18th Lok Sabha

17वीं एवं 18वीं लोकसभा के सहभागी सांसद



Shri Ramesh Awasthi
Kanpur, Uttar Pradesh



Shri Kripanath Mallah
Karimganj, Assam



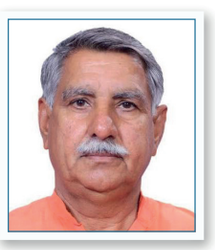
Shri Sanjay Dina Patil
Mumbai Northeast, Maharashtra



Shri Chandan Singh Chauhan
Bijnor, Uttar Pradesh



Dr. Ganapathy P Rajkumar
Coimbatore, Tamil Nadu



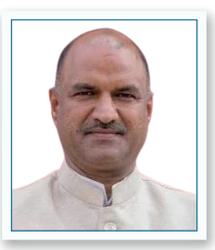
Shri Dharambir Singh
Bhiwani-Mahendragarh, Haryana



Shri Golla Babu Rao
Member Rajya Sabha, Payakaraopet, Andhra Pradesh



Shri Mukeshkumar Chandrakant
Surat, Gujarat



Shri CP Joshi
Chittorgarh, Rajasthan



Shri Parbhubhai Vasava
Bardoli, Gujarat



Shri Alok Sharma
Bhopal, Madhya Pradesh

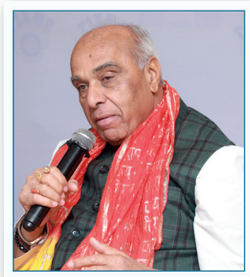


Shri Dilip Saikia
Darrang–Udalguri, Assam

Members' Perspective (1/3)

सदस्यों के विचार (1/3)

"The Forum has enabled MSMEs to engage more effectively with the parliamentary system and articulate their concerns and recommendations before policymakers. Representations made before parliamentary forums and committees have brought several critical MSME issues to the forefront of policy discussions."



Shri Jagdambika Pal
Domariyaganj (UP)

"फोरम ने एमएसएमई को संसदीय व्यवस्था के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने तथा नीति-निर्माताओं के समक्ष अपनी चिंताओं और सुझावों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। संसदीय मंचों एवं समितियों के समक्ष की गई प्रस्तुतियों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे नीति-निर्माण संबंधी चर्चाओं के केंद्र में आए हैं।"

"Friends of MSMEs in Parliament' has been consistently raising important policy issues, many of which have been duly noted by the government. FISME, serving as the secretariat to the forum, has also made valuable contributions by providing suggestions on regulatory reforms. In this context, it is important for FISME to take the lead in establishing an Arbitration Council under the guidance of this group."



Shri Sujeet Kumar
Member Rajya Sabha,
Representing Odisha

"फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट निरंतर एमएसएमई से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों को उठाता रहा है, जिन पर सरकार ने भी सकारात्मक ध्यान दिया है। फोरम के सचिवालय के रूप में FISME ने नियामकीय सुधारों संबंधी सुझाव देकर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी क्रम में, इस समूह के मार्गदर्शन में फिस्मे को एक मध्यस्थता परिषद की स्थापना में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।"

"Friends of MSMEs in Parliament' has emerged as an effective platform for influencing policy, with several of its recommendations being incorporated into recent Budgets and policy announcements. Complementing these efforts, FISME's policy studies such as Study for Quadrupling Meerut's GDP have helped advance the idea of bottom-up economic growth."



Shri Shashank Mani Tripathi
Deoria, Uttar Pradesh

"फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट" नीतिगत विमर्श को प्रभावित करने वाले एक प्रभावी मंच के रूप में उभरा है, जिसकी कई सिफारिशों को हाल के बजटों और सरकारी नीतिगत घोषणाओं में स्थान मिला है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, फोरम के सचिवालय FISME द्वारा किए गए अध्ययन—जैसे 'मेरठ की जीडीपी को चार गुना बढ़ाने की रणनीतियों पर अध्ययन'ने आर्थिक विकास की अवधारणा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।"

"MSME sector is a cornerstone of the nation's economy and plays a significant role in employment generation. Continuous dialogues and collaboration through platforms like this are essential to strengthen this sector. SAMWAD dialogues have provided in-depth discussions on policy measures required for the development of MSME sector"



Shri Jagadish Shettar
Belgaum, Karnataka

"एमएसएमई क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन का महत्वपूर्ण आधार है। इस क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए ऐसे मंचों के माध्यम से निरंतर संवाद और सहयोग आवश्यक हैं। 'संवाद' कार्यक्रमों ने एमएसएमई विकास हेतु आवश्यक नीतिगत उपायों पर सार्थक चर्चा का अवसर प्रदान किया है।"

Members' Perspective (2/3)

सदस्यों के विचार (2/3)

"The Government has placed renewed emphasis on strengthening the MSME sector and expanding self-employment opportunities. The government is committed to encourage entrepreneurship, enable enterprise growth, and help transform job seekers into job creators."



Shri Jugal Kishore
Jammu

"सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने और स्व-रोजगार के अवसरों का विस्तार करने पर विशेष बल दिया है। सरकार उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, उद्यमों के विकास को गति देने तथा नौकरी खोजने वालों को रोजगार सृजक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।"

"The need for a forum like 'Friends of MSMEs in Parliament' is widely recognized both within and outside Parliament. The Government has shown a strong commitment to addressing MSME concerns over the past decade. The Forum should now take on a greater mentorship and facilitative role to support the growth and development of MSMEs."



Shri Sudhir Gupta
Mandaur, Madhya Pradesh

"फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट जैसे मंच की आवश्यकता संसद के भीतर और बाहर व्यापक रूप से महसूस की जाती है। पिछले एक दशक में सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। अब फोरम को एमएसएमई के विकास और प्रगति के लिए मार्गदर्शक की अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।"

"Role of 'Friends of MSMEs in Parliament' is especially important in bridging the gap between MSMEs and policymakers, ensuring that the concerns of entrepreneurs are effectively represented. Such platforms are vital for shaping responsive policies and strengthening India's MSME ecosystem."



Shri Sanjay Dina Patil
Mumbai Northeast, Maharashtra

"फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट' की भूमिका एमएसएमई और नीति-निर्माताओं के बीच सेतु का कार्य करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिससे उद्यमियों की चिंताओं को प्रभावी ढंग से नीति-निर्माण तक पहुँचाया जा सके। ऐसे मंच उत्तरदायी नीतियों के निर्माण तथा भारत के एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"

"Friends of MSMEs in Parliament can play a significant role in shaping policies that drive infrastructure development in rural areas located in the vicinity of industrial clusters, thereby fostering balanced and inclusive growth."



Dr. Rajkumar Sangwan
Baghpat, Uttar Pradesh

"फ्रेंड्स ऑफ एमएसएमईज़ इन पार्लियामेंट' औद्योगिक क्लस्टरों के आसपास स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने वाली नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिससे संतुलित एवं समावेशी विकास को गति मिलेगी।"

Members' Perspective (3/3)

सदस्यों के विचार (3/3)

"Valuable suggestions are received in SAMWAD meetings regarding the challenges faced by entrepreneurs, emerging opportunities, and their empowerment. The MSME sector plays a crucial role in the country's economic development, and such dialogues are a commendable initiative."



Shri Naresh Bansal
Member of Rajya Sabha,
Representing Uttarakhand

"संवाद' बैठकों में उद्यमियों की चुनौतियों, उभरते अवसरों तथा उनके सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होते हैं। एमएसएमई क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ऐसे संवाद इस क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल हैं।"

"Government has articulated a long-term, forward-looking vision for India's growth over the next 50 years, with a strong emphasis on Make in India and Make in India for the World. In this context, FISME should consider establishing a dedicated Research Centre to build strong linkages with academic institutions."



Shri Atul Garg
Ghaziabad, U.P

"सरकार ने अगले 50 वर्षों के लिए भारत के विकास का एक दीर्घकालिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, जिसमें 'मेक इन इंडिया'और 'मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' पर भी विशेष बल दिया गया है। इस संदर्भ में फिस्मे को एक समर्पित अनुसंधान केंद्र स्थापित करने तथा शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों के साथ मजबूत सहयोग विकसित करने पर विचार करना चाहिए।"

"The forum will continue to take feedback and inputs from industry inputs from industry on how the government can transition from a scheme-based approach to a more mission-oriented framework with outcome-based incentives."



Shri Dharambir Singh
Bhiwani-Mahendragarh, Haryana

"फोरम उद्योग जगत से निरंतर सुझाव एवं फीडबैक प्राप्त करता रहेगा, ताकि सरकार योजनाओं-आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़कर परिणाम-आधारित प्रोत्साहनों वाले अधिक मिशन-उन्मुख ढांचे की ओर प्रभावी रूप से अग्रसर हो सके।"

"The government is focussing on promoting district-level growth plans and strengthening local production ecosystems, ensuring that policy interventions translate into tangible and inclusive economic outcomes, prioritising backward regions, developing integrated value chains."



Shri Ramesh
Kanpur, Uttar Pradesh

"सरकार जिला-स्तरीय विकास योजनाओं को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दे रही है, ताकि नीतिगत हस्तक्षेपों का लाभ ठोस एवं समावेशी आर्थिक परिणामों के रूप में प्राप्त हो।"

Brief About Forum and Secretariat

फोरम एवं सचिवालय का संक्षिप्त परिचय

Friends of MSMEs in Parliament

The "Friends of MSMEs in Parliament" is a prominent, cross-party forum of Indian parliamentarians established in early 2023 to advocate for the interests of the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector within the legislative process. Chaired by Shri Shankar Lalwani (MP, Indore) and convened by Shri Rajendra Agrawal (Former MP, Meerut), the group functions as a crucial bridge between small entrepreneurs and the government. Its primary mandate is to ensure that new legislations and policies reflect an "MSME perspective" to prevent regulatory hurdles that often favor larger corporations. Through its structured dialogue platform, known as SAMWAD, the forum gathers feedback from stakeholders before every Parliamentary session, leveraging standing committees and official channels to resolve systemic bottlenecks such as delayed payments, credit access, and the formalization of informal enterprises. (www.friendsofmsme.org.in)

Federation of Indian Micro and Small & Medium Enterprises (FISME)

The Federation of Indian Micro and Small & Medium Enterprises (FISME) is the leading national body for MSMEs in India. Tracing its origins back to 1967 as the National Alliance of Young Entrepreneurs (NAYE) before being rechristened in 1995, FISME represents a vast network of over 700 geographical and sectoral associations. As a non-profit and politically neutral organization, it provides the research-backed advocacy and institutional support necessary to sharpen parliamentary debates on industrial policy. FISME works closely with central ministries and bilateral and multilateral agencies to execute development projects, promote the green transition, and facilitate the adoption of digital tools and AI among MSMEs. (www.fisme.org.in)

Institutional & Strategic Partners

- Secretariat to 'Friends of MSMEs in Parliament': FISME serves as the technical and administrative secretariat for this forum, ensuring that MSME interests are effectively represented in parliamentary discussions. (www.friendsofmsme.org.in)
- Centre of Excellence for Aspiring SMEs (CoEAS): Established by FISME and IFCI (a Govt. of India undertaking), this centre focuses on equity, scaling, and technology for high-growth potential SMEs. (www.aspiringsmes.org.in)
- Centre for Improving Access to Justice (CIAJ): A specialized institution dedicated to helping small businesses navigate legal frameworks and improve access to justice.
- KNN India (Knowledge & News Network): A dedicated MSME news agency providing real-time updates and ensuring member grievances reach decision-makers. (www.knnindia.co.in)
- IPFC (Intellectual Property Facilitation Centre): Provides specialized support for patents, trademarks, and industrial designs to protect MSME innovation. (www.ipfc4msme.in)

Activities at a Glance

गतिविधियों की एक झलक



















FRIENDS OF MSMEs
IN PARLIAMENT

FRIENDS OF MSMEs IN PARLIAMENT
Secretariat: FISME, B- 4/161, Safdarjung Enclave, New Delhi - 110029, INDIA
Phone: +91 -11 - 26187948, 26712064 | Mobile: +91-9013180336
Website: www.friendsofmsme.org.in
E-Mail: secretary@friendsofmsme.org.in